पड़ोसी राज्यों के प्रति राजीव गांधी की विदेष नीति का समीक्षात्मक अध्ययन

18

डॉ. वकुल रस्तोगी *

भूमिका

पंडित जवाहर लाल नेहरू की विदेश नीति आदर्शवादी मूल्यों से ओतप्रोत थी। श्रीमती इन्दिरा गांधी की विदेश नीति व्यवहारवाद, दृढ़ता और राष्ट्रीय मूल्यों को परिलक्षित करती थी। राजीव गांधी के पास न तो पंडित नेहरू के समान राष्ट्रीय आंदोलन का अनुभव था और न ही अपार अर्जित लोकप्रियता थी। श्रीमती इन्दिरा गांधी को एक ओर राष्ट्रीय आंदोलन का अनुभव था, तो दूसरी ओर पिता के सानिध्य में रहकर बाह्य और आन्तरिक नीतियों का तजुर्बा था। राजीव गांधी को राश्ट्रीय आंदोलन का कोई अनुभव नहीं था फिर भी देश के प्रधानमंत्रियों के परिवार में जन्म लेने, पलने, बढ़े होने के कारण उनकी विचारधारा बड़ी ही स्पष्ट, राष्ट्रीय हित को सम्वर्द्धित करने वाली, इक्कीसवीं सदी की परिकल्पना से परिपूर्ण थी । वास्तव में राजीव गांधी की विदेश नीति, एक ओर परम्परागत भारतीय विदेशी नीति की विशेषताओं, जैसे . गुट निरपेक्षता की नीति, शान्ति की विदेश नीति, मैत्री और सह.अस्तित्व की नीति, पंचशील की नीति, प्रजातीय विभेद के विरोध की नीति, संयुक्त राष्ट्रसंघ के समर्थन की नीति तथा एशिया.अफ्रीका की एकता की नीति से परिपूर्ण थी, तो दूसरी ओर उनकी विदेश नीति में इक्कीसवीं सदी के आह्वान और आधुनिकता की ओर रूझान में परम्परागत विदेश नीति में लाभकारी परिवर्त्तन दिखाई दे रहे थे।

राजीव गांधी की विदेश नीति

राजीव गांधी ने अपनी विदेश नीति में पाँच तथ्यों पर विशेष रूप से बल दिया था, इन्हें हम पांच डी की संज्ञा दे सकते हैं। निःशस्त्रीकरण, उपनिवेशवाद की समाप्ति, विकास, शान्ति का राजनय तथा विश्व राजनीति में लोकतंत्र।[1] राजीव गांधी ने गुट निरपेक्षता के सिद्धांत के साथ ही सह.अस्तित्व अहस्तक्षेप और प्रजातिवाद.विरोध की नीति को अपनाया। क्योंकि सह.अस्तित्व का सिद्धांत भारतीयों के लिए स्वाभाविक है, इस संबंध में राजीव गांधी ने पेरिस में टिप्पणी की, सभ्यता की तरह जिसने भारत को जीवित बनाए रखा है, वह है उसकी स्वीकार करने, ग्रहण करने और अपनाने, विभिन्नता को सहन करने और सम्पूर्ण दृष्टि से पर्यावलोकन करने की असाधारण क्षमता का होना हमारा राजनैतिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान हमारी देशभक्ति पर आधारित है।[2] राजीव गांधी ने कहा'हमारा प्रणाली–विज्ञान समन्वय है, न कि विवाद, संवाद है न कि आधिपत्य।'[3]बहुध्रुवीय विश्व के अस्तित्व को पहचान कर राजीव ने सहयोग को अनिवार्य माना। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा, क्योंकि आज ज्ञान विज्ञान और तकनीकी के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है, इसलिए अध्यात्मिक और नैतिक ज्ञान के द्वारा मानव

*एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, मेरठ कॉलेज, मेरठ, उत्तर प्रदेश

का एक व्यक्ति के रूप में विकास होना तो दूर की बात है। इस खाई से बहुत ज्यादा सामाजिक तनाव उत्पन्न हो गया है। आज विकासशील देशों में आर्थिक विकास जिस तेजी से हो रहे है, उतने सौ साल पहले विकासशील देशों में नहीं होते थे। इन परिवर्तन के कारण, राष्ट्र डर के कारण अपने इर्दगिर्द अर्थव्यवस्था की दीवारें निर्माण करने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए हमारा यह दायित्व है कि हम विकास की अंधाधुंध दौड़ में शामिल न हों बल्कि अपने संसाधनों का समयानुसार प्रयोग करके लक्ष्य को प्राप्त करे। विभिन्न देशों में इस तेज और असंतुलित विकास के कारण ही राजीव यह मानते थे कि एक देश के काम में दूसरे देश का हस्तक्षेप न होना समय की मांग है। यहां तक किबिना ऐतिहासिक परिस्थितियों के हस्तक्षेप अक्सर अनावश्यक होता है। इस सिद्धांत का समर्थन करने के लिए राजीव गांधी ने न्यूयार्क में महात्मा गांधी के कथन को उद्धृत किया''मैं भारत को तभी अखंड रख सकता हूँ, जबकि संपूर्ण मानव परिवार के प्रति मैं अच्छी भावना रखूंगा, लेकिन केवल उसी मानव परिवार के लिए नहीं जो पृथ्वी के उस छोटे से हिस्से में रहते हैं जिसे भारत कहते हैं।' अहस्तक्षेप के सिद्धांत को बनाए रखते हुए राजीव गांधी ने खुलेआम पाकिस्तान का भारत में हस्तक्षेप को गलत माना, जबकि उन्होंने पाकिस्तान के समक्ष दोस्ती का प्रस्ताव रखा था। ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा निकारागुआ में कौण्टरास के आर्थिक प्रोत्साहन के विरुद्ध कहा, अफगानिस्तान में रूस के आक्रमण और संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट किया। भारतीय समुद्र को शांति का क्षेत्र बनाए रखने के लिए भारत की इच्छा के बारे में बात करते हुए राजीव ने अक्सर भारत के आसपास के क्षेत्र में बढ़ते ध्रुवीकरण की निंदा की जो अपने पास के क्षेत्र में शांति का बोझ डालते हैं, जैसे कि महाशक्तियाँ अपने स्वार्थ के लिए करती हैं। यद्यपि वह यह मानते थे कि आज जिस सार्वभौमिक नीति की आवश्यकता है, उसका आधार संयुक्त राष्ट्र हो सकता है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र शासनपत्र का सार शांतिपूर्वक सहअस्तित्व है और सहअस्तित्व को सबसे बड़ा खतरा प्रतिद्वंद्वी सैनिक गुटों से है।[4]

पड़ोसी राज्यों के प्रति राजीव गांधी की विदेश नीति

दिसम्बर 1984 में जब से राजीव गांधी सत्ता में आए तब से भारतीय विदेश सम्बन्धों में उन देशों में साथ जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण थे, न तो संदिग्धता रही है, न ही अनिश्चितता[5] और पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों में एक निरंतरता चाहते थे, देश में गांधी ने ऐसे सरकारी ढांचे को बनाने का आह्वान किया, जिसका प्रशासन प्रजातांत्रिक रूप से युवा पीढ़ी के पुरूषों और महिलाओं द्वारा होगा, जो अधिक संगठित भारत और अधिक संगठित विश्व का सपना देखते हैं। राजीव ने विदेश संबंधों में असाधारण स्वतंत्रता की शैली प्रदर्शित की। कई पश्चिमी देश उनकी विदेश नीति में असाधारण निरंतरता को पहचानने में असफल रहे। हालांकि भारत की विदेश नीति की स्पष्ट विचारधारा राजीव के वक्तव्य व कार्य में उतनी ही सशक्त थी, जितनी कि नेहरू की थी। राजीव के अपने शब्दों में ''हम विश्व को यह दिखाने की पहल कर रहे हैं कि भारत वास्तव में क्या हैघ् वह नहीं जो मीडिया के द्वारा बताया जाता है।''[6] राजीव की विदेश नीति विस्तृत रूप से वंशानुगत है। जो कि उनके नाना जवाहर लाल नेहरू तथा माँ श्रीमती इंदिरा गांधी के नक्शे.कदम पर चलने के लिए प्रेरित करती

है। राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद किस विदेश नीति का पालन किया तथा उनके समय के विश्व के अन्य देशों के साथ कैसे संबंध थे उनका वर्णन निम्नलिखित है

पाकिस्तान के प्रति विदेश नीति

प्रधानमंत्री पदग्रहण करने के मात्र 13 दिन बाद ही 12 नवम्बर 1984 को राजीव गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हम अपने निकट पड़ोसियों में से प्रत्येक के साथ शान्ति मित्रता और सहयोग के रूप में घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहते हैं। ये वे ही बातें हैं, जिन्हें हमने पाकिस्तान के सम्मुख प्रस्तुत किया है। हम सदा से विश्वास करते हैं कि अहस्तक्षेप शान्तिपूर्ण सह.अस्तित्व और गुटनिरपेक्षता हमारे संबंधों के मार्ग प्रदर्शक सिद्धान्त रहे है, और होने चाहिए।[7]राजीव गांधी के काल में जनवरी 1985 में भारत.पाक संयुक्त आयोग की तीन दिवसीय बैठक हुईए जिसमें दोनों देशों में कृषि अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में आपसी सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए गएण् साथ ही सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में आपसी आदान.प्रदान बढ़ाने तथा यात्रियों को नई सुविधाएं देने में समझौते एक दूसरे के परमाणु आदान–प्रदान किया।

राजीव गांधी के भारत.पाक संबंध सुधारने के अथक प्रयास के बावजूद कुछ ऐसी घटनाएं घटी। जिससे दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण होने लगे। इसी बीच सितम्बर 1986 में पाकिस्तान के आतंकवादी अपहरणकर्ताओं ने एक भारतीय विमान को अपहरण कर उसे कराची ले गए तथा उसमें सवार 77 भारतीयों की हत्या करी गई। दिसम्बर 1986 में दोनों देशों के बीच तनाव में और वृद्धि हो गईए जब पाकिस्तान में सैनिक अभ्यास के नाम पर अपने 19 डिवीजन सेना में से 17 डिवीजन सेना को भारत.पाक सीमा पर लगा दिया। इससे वातावरण अत्यधिक गर्म हो उठा और ऐसा लगने लगा कि भारत.पाक युद्ध अब दूर नहीं है। परन्तु राजीव गांधी के प्रयास से युद्ध के बादल हटने लगे तथ दोनों देशों के विदेश सचिवों के मध्य पाँच दिनों की बातचीत के बाद 4 फरवरीए 1987 को एक समझौता हो गया और युद्ध का खतरा टल गया।[8]

1988 के प्रारम्भ में दोनों देशों के बीच सीमा पर छिटपुट गोलाबारी सियाचीन क्षेत्र में हुई। 20 अप्रैलए 1988 को लोकसभा में बहस को उत्तर देते हुए राजीव गांधी ने दुःख प्रकट किया कि यद्यपि भारत पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारना चाहता है तथापि पाकिस्तान से इसकी उचित प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो रही है। उन्होंने संसद में कहा, हमने शान्ति और मित्रता की संधि का प्रस्ताव रखा है, हमने आणविक प्रतिश्ठानों का अनाक्रमण समझौते का प्रस्ताव रखा है, हमने हवाई अपहरण का उल्लंघन नहीं करने का प्रस्ताव रखा है हमने व्यापार में सबसे अधिक अनुग्रह वाली सूची में पाकिस्तान को रखने का प्रस्ताव दिया है, हमने भारत पाकिस्तान संयुक्त उद्यम का प्रस्ताव रखा है। इसी प्रकार लेखकों, विद्वानों, अखबारनविसों सांस्कृतिक मंडलियों, फिल्मों, नाटकों, संगीत और नाट्य क्षेत्रों में आदान प्रदान का प्रस्ताव रखा है, हमने पुस्तकोंए पत्रिकाओं और समाचार.पत्रों के आदानप्रधान का प्रस्ताव रखा है, हमने अपने आपसी विश्वास निर्माण और खतरा घटाने वाले उपायों को प्रस्ताव के रूप में रखा है जिस पर आपस

में सहमति हो जाए। हमने यात्रा प्रतिबंधों को आसान करने का प्रस्ताव भी रखा है, हमने नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद को रोकने में सहयोग करने का प्रस्ताव भी रखा है।[9]परन्तु राजीव गांधी ने दुरूख प्रकट किया कि पाकिस्तान की तरफ से इन पर संतोशजनक उत्तर नहीं मिला बल्कि उसने आणविक अस्त्रों का कार्यक्रम तैयार कर लिया हैं। इससे सियाचीन के क्षेत्र में शत्रुवत वातावरण उत्पन्न हो गया है।

अगस्त 1988 में जनरल जिया.उल.हक की मृत्यु विमान दुर्घटना में हो गई। राजीव गांधी उनके अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए पाकिस्तान गएए यह राजीव गांधी के मानवीय मूल्यों की अभिव्यक्ति थी। 2 दिसम्बरए 1988 को पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टों के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। ऐसा लगा कि द्विपक्षीय संबंध में दोनों देशों के बीच संबंध सुधरेंगे। सार्क की बैठक जो 29 दिसम्बरए 1988 में इस्लामाबाद में हुईए इसके अन्तिम दिन 31 दिसम्बर को बेनजीर भुट्टो ने राजीव गांधी के साथ तीन बैठक कीए जिसमें तीन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टों इन समझौतों पर हस्ताक्षर के समय उपस्थित थे। इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण समझौता दोनों देशों के बीच एक दूसरे के परमाणु संस्थानों पर हमला नहीं करने से सम्बद्ध था। इस समझौते में यह भी व्यवस्था की गई कि दोनों देशों को प्रतिवर्ष । जनवरी को यह बताना होगा कि उनके परमाणु संयंत्र किस अक्षांश तथा किस देशान्तर में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई भी अपने परमाणु संयंत्र को कहीं और स्थापित करता तो भी उसकी जानकारी दूसरे देश को देनी होगी।

राजीव गांधी ने पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने का अथक प्रयास किया। परन्तु पाकिस्तान एक ओर मीठी.मीठी बातें कर रहा था, तो दूसरी ओर पंजाब और कश्मीर में आतंकवादियों को हर दृश्टि से सहायता और प्रोत्साहन दे रहा था। फलतरू राजीव गांधी के भरपूर प्रयास के बाद भी भारत.पाक संबंधों में विशेश सुधार नहीं हो सका। पाकिस्तान ने राजीव गांधी के बढ़े हुए मित्रवत हाथ को नहीं पकड़ा और वह अपने को कश्मीर और पंजाब के उग्रवादियों को सहायता देने में लगा रहा। ऐसे ही वातावरण में भारत में आम चुनाव हुए तथा नए चुनाव में कांग्रेस की हार के कारण राजीव गांधी को 5 दिसम्बरए 1989 को प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा।

श्रीलंका के प्रति विदेश नीति

राजीव गांधी श्रीलंका की घटनाओं से बड़े ही दुःखी थे। 11 दिसम्बरए 1984 को नई दिल्ली में एक वक्तव्य में उन्होंने कहा, 'मैं इस बात से गम्भीर रूप से चिन्तित हूँ कि श्रीलंका की स्थिति तीव्रता से बिगड़ रही है। उत्तरी तथा पूर्वी प्रान्तों में हिंसा में तीव्र बढ़ोतरी हुई है, जिसमें बहुत से निर्दोश लोगों की जाने चली गई है। भारतीय मूल के अनेक तमिल जो इस क्षेत्र में बसे है, इस हिंसा का भी शिकार हो रहे हैं। सुरक्षा सेनाएँ अविवेक से हत्याएँ कर रही हैं। जाफना प्रायद्वीप में सुरक्षा क्षेत्र की उद्घोशणा के बाद से जाफना शहर पूर्णतरू उनके कब्जे में है, खाद्यान्न की अत्यधिक कमी हो गई है, सैकड़ो नौजवानों को पकड़कर बंदी बनाया

गया है तथा उन्हें अज्ञात स्थानों पर हस्तान्तरित कर दिया गया है।[10] इस पृष्ठभूमि में राजीव ने श्रीलंका के साथ संबंधों को सुधारने की पहल प्राथमिक रूप से राजीव–जयवर्द्धन समझौते के रूप में सामने आयी।

भारत और श्रीलंका के बीच तमिलों को लेकर जातीय समस्या थी और ऐसा लगने लगा था कि समस्या और भी उलझती चली जा,गीए क्योंकि और एक ओर जयवर्धनें कीसरकार जातीय वध पर अडिग थी, तो दूसरी ओर राजीव गांधी भी अपने आदर्शों और सिद्धान्तों पर अडिग थे। 5 जून, 1987 को राहत सामग्री एवं दवाएँ भेजने के मात्र 1 माह और 24 दिन में ही एकाएक एक चमत्कार हो गया और 29 जुलाई, 1987 को भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धनें के बीच कोलम्बों में एक 18 सूत्रीं समझौता हो गया। चूंकि यह समझौता कोलम्बों में हुआ, इसलिए इसे कोलम्बो समझौते की संज्ञा दी जाती है। समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धनें द्वारा दिए गए भोज में राजीव गांधी ने कहा, हम एक समझौते पर पहुँच गए हैं, यह दोनों देशों के इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण घटना है। यह श्रीलंका में राष्ट्रीय समाधान का वादा करता है। इसने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की है, जिससे कि शरणार्थो वापस लौट जाए इसने उन बादलों को छाँटा है, जिसने हमारे संबंधों को ढक लिया था मैं राष्ट्रपति जयवर्धनें के साहस तथा राजनीति को व्यक्तिगत रूप से सराहना करना चाहूँगा। यह समझौता उनके मैत्रीए करूणा एवं समन्वय के महान मूल्यों में विश्वास प्रकट करता है। श17 अपने सम्बोधन के अंत में राजीव गांधी ने सुब्रमन्यम भारती की कविता को पढ़ा कि यही हम लोगों का पथ प्रदर्शन करें। इस कविता में कहा गया है, एक साथ रहना ही असली जीवन है, अलग.अलग हो जाना बर्बादी है, यह पाठ अवश्य पढ़ना चाहिए इससे अधिक कोई ज्ञान नहीं चाहिए।

श्रीलंका की बहुसंख्यक सिहंली जनता ने इस समझौते का घोर विरोध किया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री प्रेमदासा और आन्तरिक सुरक्षा मंत्री असंतुलन मुदानी ने इससे अपने को पूर्णरूप से अलग रखा।परन्तु सच्चाई यह है कि इस समझौते को दोनों देशों के नेताओं के साहस एवं सूझबूझ का परिणाम कहना ज्यादा न्यासंगत होगा। इस समझौते को राजीव गांधी की एक महान राजनयिक सफलता कहा जा सकता है। इस समझौते ने श्रीलंका का, कम से कम राष्ट्रपति जयवर्धने का, पाकिस्तान तथा पश्चिम की ओर बढ़ रहे झुकाव को समाप्त करए उन्हें भारतीय प्रभामंडल में खींच लिया। इस दृश्टि से 2 अक्टूबरए 1988 में मतदान के समय तमिलनाडु में राजीव गांधी की यह उक्ति शत प्रतिशत सत्य प्रतीत होती है, जब उन्होंने कहा था, भारत. श्रीलंका समझौते द्वारा श्रीलंका में तनाव एकाएक और सारपूर्ण रूप से कम हो गया। यह भारत की विदेश नीति में एक ऐतिहासिक सीमा चिह्न है।[11]

श्रीलंका पर राजीव द्वारा किए गए समझौते की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा की गई। और इस बारे में व्यापक मतैक्य यह था कि समझौते के पूर्णरूपेण कार्यान्वयन से सबको लाभ होगा, क्योंकि तमिल लोगों की आकांक्षाएँ पूरी होगी। श्रीलंका की एकता और अखंडता बनी रहेगी। और इस क्षेत्र में शांति और स्थायित्व कायम होगा। हालांकिए यद्यपि भारत के संदर्भ में सुरक्षा की बातें भी पूरी हो जाएगी तथापि तमिल मुक्ति चीतों ने शांति स्थापित करने की बात

को समाप्त कर दिया। राजीव जी ने कहा कि यह अत्यंत खेदपूर्ण बात है कि तमिल मुक्ति चीतों में इन सबकी उपेक्षा कर दी है। उन लोगों ने यह सब जान.बूझकर समझौता तोड़ने के लिए किया है क्योंकि वे लोग उग्रवाद को छोड़कर जनतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया स्थापित नहीं करना चाहते। ये तमिल मुक्ति चीतों का एक ऐसा गिरोह है जो बूढ़ोंए बच्चों और महिलाओं को अपनी ढाल बनाकर भोले–भाले बच्चों को मानव बम बनाकर कैदियों की हत्या कर आफना के लोगों केए जिनके हितार्थ वे लड़ने का दावा करते हैं, हर मापदंड का उल्लंघन किया है। तमिल मुक्ति चीतों ने जो इच्छा व्यक्त की हम लोगों ने उपलब्ध कराया। जिस पर मुक्ति.चीतों की अनुक्रिया यह रही कि उन्होंने धमकियों, नए सिरे से प्रचार, गलत और मिथ्या सूचनाएं देना आरंभ कर दिया ताकि भारत एवं उसके सैनिकों की छवि धूमिल हो जाए। फिर भी हम आशा करते हैं कि उन्हें सद्बुद्धि मिलगी।[12] परन्तु आशा पर तुशारापात हो गया, और राजीव जी स्वयं मुक्ति चीतों के षडयंत्र के शिकार हो गए।

चीन के प्रति विदेश नीति

भारत और चीन के संबंध को हम तीन कालों में विभाजित कर सकते हैं। पहला कालए सन् 1949 से 1957 तक के काल को प्रमोद काल की संज्ञा दी जाती है। दूसरा कालए जो 1957 से 1978 तक का काल था, टकरावए युद्ध तथा तनाव का काल था। इस काल में एक ओर तिब्बत के प्रश्न पर दोनों में मतभेद थे, तो दूसरी ओर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद प्रारम्भ हो गए। चीन ने भारत के एक विशाल भाग को अपनी भूमि के रूप में दर्शाया। इसके बाद अक्टूबर 1962 में चीन ने बड़े पैमाने पर भारत पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में भारत पराजित हो गया तथा दोनों देशों के संबंध करीब.करीब समाप्त हो गए। तीसरा काल का प्रारम्भ 1977 से होता है, जब भारत में श्री मोरारजी देसाई के नेतष्त्व में जनता पार्टी की सरकार बनी और भारत ने विगत बातों को भुलाकर चीन के साथ नए सिरे से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। दूसरी ओर चीनए भारत की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाने के लिए अनेक आन्तरिक तथा बाह्य कारणों से विवश हो गया। चीन जानता था कि भारत प्रभाव क्षेत्र की राजनीति एवं महाशक्तियों के प्रसार का विरोधी है, इसलिए भारत के साथ मिलकर ही एक सक्षम एशियाई व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है, जिससे कि एशिया में बड़ी शक्तियों के प्रसार तथा प्रतिस्पर्धा को रोका जा सकता है।चीन के मस्तिश्क में यह बात स्पश्ट थी कि भारत के साथ संबंध सुधारना ही चीन के राष्ट्रहित में है।

राजीव गांधी की पहल पर 23 नवम्बर 1985 को भारत और चीन के बीच एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके अन्तर्गत वर्ष 1986 के दौरान दोनों देश के बीच 1 से 14 करोड़ रूपये का व्यापार होना निर्धारित किया गया। इस समय व्यापार संतुलन 10 चीन के पक्ष में था। 1984–85 में भारत ने चीन को 65.55 करोड़ रूपये का माल आयात किया, जबकि निर्यात मात्र 2.12 करोड़ रूपये का था। नए समझौते से व्यापार संतुलन स्थापित होने की आशा प्रकट की गई। दोनों देशों के बीच 19 जुलाई 1986 को बीजिंग में वार्ता का सातवां दौर प्रारम्भ हुआ। इस वार्ता में चीन द्वारा 30 जून 1986 को भारतीय सीमा में की गई घुसपैठ पर चिन्ता व्यक्त की गई। 20 जनवरी 1987 को विज्ञान भवन में पत्रकारों के प्रश्नों के जवाब

में राजीव गांधी का उत्तर था, हम चीन के साथ सुंगदुराग घाटी में अतिक्रमण के संबंध में सम्पर्क में है। इसका हल उनसे बातचीत के द्वारा ही हो सकता है और हम आशा करते हैं कि हम चीन से बातचीत कर इसके समाधान में समर्थ होंगे।

राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 20 फरवरी 1987 को भारत ने अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ का 24वाँ राज्य घोषित किया तो 21 फरवरी 1987 को चीनी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, भारत की इस कार्यवाही से चीन को प्रादेशिक अखण्डता एवं सम्प्रभुता का गम्भीर उल्लघंन हुआ है। दूसरी ओर भारत ने चीन के इस विरोध को घरेलू मामले में हस्तक्षेप की सझा दो। राजीव गांधी ने 23 जुलाई 1988 को हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली के सम्पादक श्री एस०के० दुआ को साक्षात्कार देते हुए कहा था, जहाँ तक हमारा संबंध है, अरूणाचल प्रदेश की स्थिति यह है कि वह भारत का अभिन्न भाग है और इस पर किसी से कोई बातचीत नहीं हो सकती। हम किसी भी वैसी स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकते जो इस तथ्य को संदेह के घेरे में डाल दें। राजीव गांधी इस बात से अवगत थे कि चीन की स्थिति विश्व में एक शक्तिशाली राज्य की है। चीन के इतिहास की तुलना अपने पड़ोसियों के प्रदेशों को धीरे–धीरे कुतरने की पत्ता हाथी घास (एक प्रकार का पौधा) को खाने से की गई है। ऐसी स्थिति में भी भारत के प्रभावशाली जनमत के एक वर्ग और दल के मना करने पर भी दिसम्बर 1988 को राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में चीन जाने का निर्णय लिया। इस निर्णय के तहत 1988 को राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में चीन की पाँच दिवसीय यात्रा की। पिछले 34 वर्षों में भारत के किसी प्रधानमंत्री की यह पहली चीन यात्रा थी। अक्टूबर 1954 में पंडित जवाहर लाल नेहरू चीन की यात्रा पर गए थे। उसके कुछ दिनों बाद भारत तथा चीन के संबंध इस प्रकार तनावपूर्ण होते चले गए कि भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने चीन की यात्रा नहीं की। राजीव गांधी की चीन के राश्ट्रपति याँग–शान–कुन, चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग तथा चीन के शीर्ष नेता सिमाओं पिंग से लम्बी बातचीत हुई। 84 वर्षीय चीनी नेता डेंग जियाओं पिंग से राजीव गांधी की 90 मिनट तक बातचीत हुई। डेंग ने राजीव गांधी का हाथ अपने से लेकर उन्हें 'मेरे युवा मित्र' से सम्बोधित किया और कहा 'हमें अतीत को भूल जाना चाहिए सीख सकते हैं .. हम दोनों ने ही गलतियाँ की हैं और एक दूसरे से आप युवा हैं आप भविष्य हैं, हम इतिहास में परावृत्त हो रहे हैं, अब नेताओं की नई पीढ़ी आ गई है तथा विश्व की इच्छा शान्ति में रहने की है, और संघर्ष तथा तनाव को समाप्त करने की है। अब यह आपके हाथ में है कि नई विश्व व्यवस्था के प्रारब्ध (भाग्य) को किस प्रकार का आकार दे, बुद्धिमानी पूर्वक इसका प्रयोग करें।[13] राजीव गांधी ने 21 दिसम्बर 1988 को बीजिंग के शिगुआ विश्वविद्यालय में भाशण करते हुए कहा, "हमें विगत के दलदल में नहीं फंसना चाहिए। भारत और चीन को आगे देखना चाहिए पीछे नहीं, जिससे कि हम नए क्षितिज में पहुँच सके। हमें मित्रता तथा सहयोग के नए आयाम को प्राप्त करना चाहिए। नए मार्ग ढूंढ़ने चाहिएँ, जिससे दोनों को और विश्व को लाभ हो सके।[14]

राजीव गांधी की यात्रा के बाद दोनों देशों की ओर से 23 दिसम्बर 1988 को जारी संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया, "राजीव गांधी की चीनी नेताओं से हुई बातचीत मैत्रीपूर्ण,

स्पष्टवादिता तथा आपसी सूझबुझ के माहौल में हुई'[15] भारत और चीन ने इसी संयुक्त वक्तव्य के अनुसार एक संयुक्त कार्यदल का गठन किया, जो सीमा विवाद का सर्वमान्य समाधान निकालेगा। राजीव गांधी की चीन यात्रा की एक और बड़ी उपलब्धि आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी तथा सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त आयोग का गठन रहा है। दोनों देशों के बीच एक संयुक्त समिति भी गठित करने का फैसला किया गया था, जो कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा आर्थिक क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोगों की सम्भावना का पता लगाने वाली थी। इसे भारत चीन संबंधों के सुधार में एक महत्त्वपूर्ण कदम माना गया।

राजीव गांधी की इस चीन यात्रा में दोनों देशों के बीच नागरिक उड्डयन सेवाओं तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्च स्तरीय सहयोग एवं सांस्कृतिक आदान–प्रदान के लिए कुछ अन्य समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए। वायु सेवाओं के संबंध में किए गए समझौते के अन्तर्गत दोनों देश नई दिल्ली और बीजिंग के बीच सीधी विमान सेवाएँ, प्रारम्भ करने के प्रश्न पर सिद्धान्त के रूप में सहमत हो गए। सांस्कृतिक समझौते के अन्तर्गत नृत्य संगीतदलों, कलाकारों तथा लेखकों का एक दूसरे के देशों में आना जाना एक दूसरे के देशों में कला प्रदर्शनियों का आयोजन करना, फिल्म सप्ताह का आयोजन करना, छात्रों तथा विद्वानों का एक दूसरे के देशों में आना जाना तथा एक दूसरे देश के साहित्य का अनुवाद एवं प्रकाशन आदि तथ्य रखे गए। एक अन्य महत्त्वपूर्ण उपलब्धि यह रही है कि दोनों देशों के बांच सौधी टेलीफोन सेवा भी इस ऐतिहासिक यात्रा के अवसर पर प्रारम्भ हो गई। राजीव गांधी ने चीन के साथ बिगड़े हुए संबंध को इस प्रकार सुधारा कि उनकी मृत्यु के बाद चीन के उपप्रधानमंत्री हुआँ कुआँ ने कहा था, 'जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने हमारे दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग को घनिष्ठ बनाने में महान योगदान दिया. मैं दुःख से स्तब्ध हो गया, जब मैंने उनकी राजनीतिक हत्या का समाचार सुना।[16] चीन के प्रधानमंत्री दुःख ली पेंग ने कहा था, श्री राजीव गांधी भारत के एक विशिष्ट राजनीतिज्ञ थे और चीनी लोगों के सुपरिचित मित्र थे, जिन्होंने चीन भारत संबंध को सुधारने तथा विकसित करने में अपना सकारात्मक योगदान दिया।

सन्दर्भ

1. मार्क टुली तथा जहीर मसानी, फ्रॉम राज टू राजीव, युनिवर्सल बुक स्टाल, नई दिल्ली, 1996, पृ. 166
2. कैथलीन हीले, राजीव गांधी, द ईयर्स ऑफ पावर, विकास पबिलिशं हाउस, नई दिल्ली, 1989, पृ. 152
3. वही, पृ. 53
4. विपिन चन्द्रा, राजीव गांधी : आधुनिक भारत के निर्माता, कलिंग पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1987, पृ. 5
5. आदिश अग्रवाल, राजीव गांधी एक ऐसेस मेकर, अमिट पब्लिकेशनंस, नई दिल्ली 1993, पृ. 56

6. वही, पृ. 75
7. शर्मा, प्रभुदत्त, अंतर्राश्ट्रीय राजनीति, कॉलेज बुक डिपो, राजस्थान, जयपुर, 1989, पृ. 473
8. नन्दा, के.के., कैनवंरिग कश्मीर ए पाकिस्तानी, आबसेशन लांसर बुक्स, नई दिल्ली, 1996, पृ. 297
9. शर्मा, प्रभुदत्त, पूर्वोक्त, पृ. 475
10. गिल, एस.एस., द डायनेस्टी, हार्पर पब्लिशर्स इण्डिया, नई दिल्ली, 1996, पृ. 166
11. शर्मा, प्रभुदत्त, पूर्वोक्त, पृ. 477–478
12. पीयूश, जगदीश, राजीव गांधी और पंचायती राज, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2008, पृ. 39
13. हीले, कैथलीन, पूर्वोक्त, पृ. 73
14. गिल, एस.एस., पूर्वोक्त, पृ. 76
15. वही
16. शर्मा, प्रभुदत्त, पूर्वोक्त, पृ. 479